जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:265 दिनांक:06-09-2024 शुक्रवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

भारत व सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर में इकोसिस्टम स्थापित करने हेल्थ सेक्टर प्रौद्योगिकी व वाणिज्यक क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से युवा श्रम को प्रशिक्षण देने और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े चार सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में दिवंगत कांग्रेस नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी से महाराष्ट्र में सभी से माफी मांगने की मांग की.

पीएम मोदी का विजन.....हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते

अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग को दिया धन्यवाद

सिंगापुर,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी वोंग के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हैं। वोंग के साथ वार्ता से पहले पीएम मोदी का सिंगापुर संसद भवन में औपचारिक स्वागत हुआ।

उन्होंने वहां आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात वोंग के सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनने और मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के कुछ दिनों बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी बाद में मुलाकात करने वाले है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में अपने समकक्ष वॉन्ग के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की जमकर तारीफ कर सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। आपके (लॉरेंस वॉन्ग) के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में सिंगापुर और तेजी से विकास करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ सहयोगी देश ही नहीं है बल्कि यह हर विकासशील देशों के लिए प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उत्पादन को आधुनिक बनाने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग, भारत-सिंगापुर के बीच होने वाली मंत्री स्तर की गोलमेज बैठक की पहचान बन गया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व मामलों के विदेश सचिव जयदीप मजूमदार और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी बैठक में मौजूद रहे। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के पीएम के साथ सेमीकंडक्टर कंपनी एईएम होल्डिंग लिमिटेड के प्लांट का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगरत्नम और वरिष्ठ मंत्री गोह चोक तोंग और विभिन्न कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात की।

चार समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच चार अहम समझौतों पर भी सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने है। समझौते के तहत भारत और सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलेपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है।

किसानों को देगी मोदी सरकार सौगात.....मिलेगा यूनिक किसान आईडी कार्ड

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए नई पहल शुरू की है। अब मोदी सरकार किसानों को यूनिक किसान आईडी कार्ड देने की तैयारी कर रही है। यह कार्ड आधार कार्ड जैसा ही होगा।

मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि अगले तीन साल तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। वहीं, चालू वित्त वर्ष को लेकर केंद्र का लक्ष्य है कि 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। यह कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा। यह कार्ड के जरिये किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा।

यह कार्ड किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के द्वारा केंद्र सरकार को पता चल जाएगा किसान के पास कितनी जमीन, मवेशी है। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा।

यह कार्ड सरकार के साथ किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित रहेगा। कार्ड के द्वारा किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहां तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी मिलेगी।

मोदी सरकार ने 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन नामक योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है। यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है।

हरियाणा में भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की, दूसरे ही दिन शुरु हो गई बगावत, दो नेताओं ने दिए इस्तीफे

चंडीगढ़(ईएमएस)। बीते रोज यानी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा इस पहली सूची के जारी होते ही बगावत भी शुरु हो गई है। रतिया विधानसभा से भाजपा ने मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया और इसके बाद विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रतिया सीट से भाजपा ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को चुनावी मैदान में उतारा है। विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट कटने के ठीक बाद प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को पत्र लिखा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में नापा ने लिखा, वह भाजपा कि वह भाजपा के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। इसी तरह, अब पूर्व मंत्री कर्ण देव कंबोज ने भी भाजपा से इस्तीपा दे दिया है। वह हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज करनाल की इंद्री विधानसभा से टिकट चाह रहे थे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कर्णदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दिया है और कहा कि समर्थकों के अनुसार वह आगामी फैसला लेंगे।

गौरतलब है कि फतेहाबाद के रतिया विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मण नापा ने पहली बार कमल खिलाया था। यहां से वह 2019 में 1216 वोटों से जीते थे। इससे पहले भाजपा इस सीट पर कभी नहीं जीती थी। 2009 में यह विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। कर्णदेव कंबोज 2014 में चुनाव जीते थे और खट्टर सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे। लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण देव कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखा कि भाजपा अब दीन दयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी नहीं रही और ऐसे में वह प्रदेशाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा अपने पद तथा भाजपा के सभी अन्य पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तव्वजो दी जाती है। कंबोज ने कहा कि साथियों वर्षों तक मैने तथा मेरे पूरे परिवार ने भाजपा की तन मन धन से सेवा की। पिछले पांच साल तक मोर्चे के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में प्रवास तथा इस समय हरियाणा में 150 सामाजिक टोलियां बना कर काम पर लगी हुई हैं, लेकिन अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली भाजपा को शायद अब वफादारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के सहारे सरकार बनाना चाहती है जिन्होने हमेशा पार्टी को नुकशान पहुंचाया है। जो कि कभी बन नहीं पाएगी। ऐसे नेता, जो कल पार्टी में आए, उन्हें टिकट दी गईं और जो बचपन से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें दर किनार कर दिया है। फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह गया है। बाकी, आगे का फैसला मेरे समर्थक लेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना।

'जात' देखकर जान ली गई -सुलतानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुलतानपुर में डकैती के एक आरोपी के पुलिस ने एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने अपने पर एक्स हैंडल पर लिखा है कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नक़ली एनकाउंटर से पहले 'मुख्य आरोपी' से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ़ दिखावटी गोली मारी गयी और 'जात' देखकर जान ली गई।

उन्होंने कहा कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवज़ा अलग से देना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे।

अखिलेश ने कहा कि नक़ली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नक़ली एनकाउंटर नहीं, असली क़ानून-व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुँच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नक़ली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है।

दरअसल, 28 अगस्त को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पांच बदमाशों ने असलहे के बल पर करोड़ों का जेवरात और नगदी लूट ले गए थे। मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि घटना में कुल 15 बदमाश प्रकाश में आए।

ट्रेनों में वसूली करने वाले किन्नरों के खिलाफ रेलवे ने चलाया अभियान 59 को पुलिस ने पकड़ा

नई दिल्ली(ईएमएस)। किन्नरों द्वारा यात्रियों को परेशान शिकायतें लगातार मिल रही हैं। बड़े स्टेशनों के आसपास से किन्नर ट्रेनों में सवार हो जाते हैं और आउटर पर पहुंचने पर उतर जाते हैं। जिससे ये स्टेशनों में पकड़ में नहीं आते हैं। इनको पकड़ने के लिए आरपीएफ चलती ट्रेनों में अभियान चला रहा है। यात्रियों को सुविधजनक और सुरक्षित यात्रा करने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। रेलवे किन्नरों के अलावा भीख मांगने वाले और स्टेशनों पर करतब दिखाने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। इस तरह की शिकायतें भी रेलवे के पास आ रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इनकी वजह से कई बार ट्रेन से सामान चोरी होने की आशंका रहती है।

उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में चलने वाली ट्रेनों में किन्नरों का 'खेल' चल रहा था। सफर कर रहे यात्रियों से ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत की। इसके बाद आरपीएफ ने चेकिंग अभियान शुरू किया। जिसमें 59 किन्नरों को रंगेहाथ पकड़ा गया। इनमें से कुछ को जेल भेजा गया। रेलवे के अनुसार इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान किन्नरों द्वारा जबरदस्ती पैसे वसूलना, परेशान करना, भद्दे इशारे करना और गलत तरीके से छूने की शिकायतें आरपीएफ को मिली। इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तर मध्य रेलवे के तीनों मण्डलों प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में किन्नरों के विरुद्व चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 59 किन्नरों को रंगेहाथों पकड़ा, जो यात्रियों को भद्दे इशारे और गलत तरीके से छू रहे थे। इन पर रेल अधिनियम-1989 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इनके 6900 रुपये जुर्माना वसूला गया और 20 किन्नरों को जेल भेजा गया। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इस तरह के अभियान रेलवे के सभी 17 जोनों में चलाए जाएंगे।

आंध्रप्रदेश में भारी बारिश से 32की गई जान

नई दिल्ली (ईएमएस)। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है, जिससे राज्य के कई क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश ने निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया है, परिवहन को बाधित कर दिया है और हजारों निवासियों को विस्थापित कर दिया है। नदियों के उफान पर होने और जल स्तर बढ़ने के कारण अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और प्रभावित समुदायों को निकालने और राहत उपाय प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

आध्रं में अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश और बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और राहत शिविरों में निकाले गए लोगों की संख्या बढ़कर 45,369 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित विजयवाड़ा वाले एनटीआर जिले में 24 मौतें हुईं, गुंटूर (सात) और पालनाडु (एक) मौत हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 4 से 8 सितंबर तक उत्तरी तटीय आंध्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है।

लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव

लखनऊ (ईएमएस)। लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (22346) पर अज्ञात शख्स ने पत्थरबाजी की। यह घटना वाराणसी के आसपास हुई। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात करीब 8।15 बजे आरोपी ने पत्थर मारकर ट्रेन के सी5 के खिड़की के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इंडियन रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन नंबर 22346 पर पत्थरबाजी की गई है। ट्रेन लखनऊ से पटना जा रही थी। बनारस और काशी के बीच रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर फेंका गया। अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत आउट पोस्ट काशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच प्रभारी निरीक्षक व्यासनगर के द्वारा की जा रही है। लोकल इनपुट जुटाए जा रहे हैं और वंदे भारत में लगे कैमरे को चेक करने की कोशिश की जा रही है।

केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की जमानत पर 10 सितंबर 2024 को फैसला आ सकता है।

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित शराब घोटाल में सीबीआई ने करीबी दो साल तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और जब ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में जमानत मिली, तभी 26 जून को गिरफ्तार किया। उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया।

केजरीवाल के वकील ने किया जमानत का अनुरोध

वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई भी खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी होते हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने भी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आज अगर माननीय जस्टिस केजरीवाल को जमानत दे देते हैं, तब यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी।

एसवी राजू ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता ये लोग जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, लेकिन केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के सामने एसवी राजू ने दलील देकर कहा, केजरीवाल को लगता है कि वे असाधारण व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग नियम कानून है। गिरफ्तारी पर सुनवाई को लिए सुप्रीम कोर्ट ही एक अदालत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

देश में रेप मामले में सजा.... दूर की कौड़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में हैं। हर कोई आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रेप के मामले में आरोपियों को सजा मिलते-मिलते लंबा समय लग जाता है। जांच में देरी के कारण सालों तक मुकदमा चलता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया का फायदा आरोपियों को मिलता है। कई बार मुकदमा पूरा होने के बावजूद आरोपियों को सजा नहीं मिलती और वह आसानी से बरी हो जाते हैं।

साल 2022 में करीब 45,000 रेप के मामलों की जांच पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन केवल 26,000 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल हो सकी। यह संख्या 2022 में दर्ज घटनाओं की संख्या से भी कम थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में रेप के करीब 32,000 मामले पुलिस में दर्ज किए गए थे। हालांकि, पिछले वर्षों से लंबित 13,000 से अधिक मामले पहले से ही विचाराधीन थे, जिससे पुलिस पर करीब 45,000 मामलों की जांच का बोझ था। लेकिन दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के मामले में, 2022 में केवल लगभग 26,000 मामलों में ही चार्जशीट दायर की गई। यह उन मामलों का 60 प्रतिशत से भी कम था जिनकी उन्हें जांच करनी थी और 2022 में दर्ज घटनाओं की संख्या से भी कम थी। यह समस्या केवल रेप केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सभी 11 श्रेणियों में देखी गई है जिनका विश्लेषण किया गया है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज.....जो गलती करता है, वहीं माफी मांगता

सांगली (ईएमएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर महायुति को निशाने पर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से जुड़ी घटना पर महाराष्ट्र के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और पीएम मोदी तक ने माफी मांगी थी। वहीं अब राहुल गांधी ने कहा कि जो गलती करता है, वहीं माफी मांगता है।

राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना का जिक्र कर कहा कि मैनें अखबार में पढ़ा था कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं शिवाजी की मूर्ति के गिरने पर माफी मांगता हूं। राहुल ने कहा कि आखिर पीएम मोदी को माफी क्यों मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के माफी मांगने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है कि इसका ठेका संघ से एक व्यक्ति को दिया गया था। इस दौरान सांगली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता मंत्री पतंगराव कदम की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि कदम जी की मूर्ति 50-70 साल बाद भी यहां प्र*ह्रष्ठ शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई थी लेकिन कुछ दिनों बाद ही मूर्ति गिर गई। यह शिवाजी महाराज का अपमान है। प्रधानमंत्री को न केवल शिवाजी महाराज से बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए।

पूर्व प्रिंसिपल घोष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट....सुनवाई आज

कोलकाता (ईएमएस)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनके कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष 6 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह याचिका मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद घोष के इर्द-गिर्द बढ़ती जांच के बीच आई है।

कट्टरपंथियों के सामने झुकी कर्नाटक सरकार, हिजाब पर प्रतिबंध करने वाले प्रिंसिपल को सम्मान नहीं

उडुपी (ईएमएस)। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी एसडीपीआई के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रिंसिपल को सम्मानित करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने उडुपी जिले के कुंडापुरा पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्ण को सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार के लिए चुना था,लेकिन अब उन्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में शिक्षा विभाग हर साल शिक्षक दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल को सम्मानित करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार के लिए दो शिक्षकों का चयन हुआ था, जिसमें कुंडापुरा पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण और मैसूर जिले के हुनसुरु पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल ए. रामेगौड़ा शामिल हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि रामकृष्ण को सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार मिलेगा है, प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी एसडीपीआई ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।

दरअसल रामकृष्ण ने पीयू कॉलेज के नियमों का पालन करते हुए फरवरी 2022 में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया था। उनके फैसले के बाद पूरे राज्य में हिजाब बैन को लेकर भारी हंगामा हुआ था। रामकृष्ण ने बताया कि उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि तकनीकी कारणों से फिलहाल उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि हालांकि उनका पुरस्कार रद्द नहीं हुआ है।

दरअसल एसडीपीआई के विरोध के बाद कई कट्टरपंथी ताकतें और अन्य लोग सक्रिय हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग की आलोचना करते हुए कई पोस्ट किए गए। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक किसी भी विवाद से बचने के लिए फिलहाल रामकृष्ण को पुरस्कार न देने का फैसला किया गया है।

दो उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली (ईएमएस)। त्रिपुरा और पूरे इलाके में हिंसा समाप्त करने और शांति लाने के प्रयासों में बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्य के दो उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता हुआ। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) ने एक समझौते पर साइन किए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और उग्रवाद मुक्त नॉर्थ-ईस्ट के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा, गृह मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच बड़ा फासला था। इस पीएम मोदी ने सड़क, रेल और विमान के जरिए तब कम किया ही। साथ ही दिलों के बीच की दूरी को भी पाटने का काम किया है।

महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में मूर्तिकार गिरफ्तार

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने मूर्तिकार को गिरफ्तार कर लिया है। मूर्तिकार जयदीप आप्टे को पुलिस ने उसकी पत्नी की मदद से ही गिरफ्तार किया है। 26 अगस्त को उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही मूर्ति ढह गई थी। पुलिस ने आप्टे की तलाश के लिए 7 टीमें गठित की थीं। पुलिस का कहना है कि आप्टे ने पत्नी से संपर्क साधा था और कहा था कि वह घर लौट रहा है। इसके बाद पत्नी ने यह जानकारी पुलिस के साथ साझा कर दी।

रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आप्टे का परिवार चिंतित था और चाहता था कि वह वापस लौटकर जांच में सहयोग करे। पुलिस ने शिवाजी की प्रतिमा ढहने के बाद आप्टे और संरचना सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था। पाटिल को पिछले हफ्ते कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस घटना के आरोपियों की गिरफतारी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता प्रवीण दारकर ने कहा, जो लोग हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे उन्हें अब अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। यह सच है कि पुलिस ने जयदीप आप्टे को गिरफ्तार करने में थोड़ा समय लिया। हम गिरफ्तारी का श्रेय नहीं ले रहे हैं लेकिन पुलिस ने अपना काम किया है।

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले को लेकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें तेज

नई दिल्ली (ईएमएस)। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले को लेकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदले जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। खबरें हैं कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के कुछ नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम पर भी जोर दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान विवाद से बचने के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने की योजना बना रहा है। इधर, विपक्ष की तरफ से भी सीएम को बदले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने इस बात पर अब तक फैसला नहीं लिया है कि सिद्धारमैया की जगह कमान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सौंपी जाए या किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मौका दिया जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया की जगह शिवकुमार का नाम आगे चल रहा है। इधर, आलाकमान पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पिछड़े वर्ग के ही उम्मीदवार को पद देने की संभावनाएं तलाश रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पार्टी नेताओं का एक समूह खरगे के नाम को भी आगे बढ़ा रहा है। वहीं, एक समूह मंत्री सतीश जरकिहोली जैसे लोकप्रिय नेताओं के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

खबर है कि रविवार को वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए जरकिहोली नई दिल्ली पहुंचे थे। इसके साथ ही अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी उन्हें मौका देने का मन बना रही है। कहा जा रहा है कि उनके पास 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, जिनमें 15 अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। उनके परिवार में तीन विधायक, एक एमएलसी और एक सांसद भी है।

माना जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के भी जरकिहोली परिवार से करीबी संबंध हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी सूत्रों ने बताया है कि अगर पार्टी सिद्धारमैया की सहमति लेती है, तो जरकिहोली उनकी पसंद हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सांसद राहुल गांधी ने भी राज्य में राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर जरकिहोली से चर्चा की है।

सेना का वाहन खाई में गिरा.....चार जवानों की मौत

पेडोंग (ईएमएस)। सिक्किम के पाकयोंग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, हादसे में भारतीय सेना के चार जवानों की मौत हो गई है। जवान पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के जुलुक सिल्क रूट से पाकयोंग की ओ जा रहे थे तभी वाहन खाई में जा गिरा हादसे में वाहन में सवार चार जवानों की मौत हो गई है।

सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में 700 से 800 फीट नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसा दलोपचंद दारा के पास वर्टिकल वीर में हुआ है। यह सिल्क रूट के नाम से मशहूर रेनॉक रोंगली हाईवे के पास पड़ता है। वाहन के खाई में गिरने से हादसे में चार जवानों ने अपनी जान गंवा दी है।

दुनिया की बुरी ताकतों का पतन भारत में होता : भागवत

नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में पनपने वाली बुरी ताकतों का पतन भारत में होता है। उन्होंने कहा कि बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं और उनके बुरे काम हर जगह जारी हैं।

भागवत सद्गुरु समूह द्वारा आयोजित 'वेदसेवक सम्मान सोहाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान 16 महीने तक वेदों के 'अनुष्ठान' (पाठ) में भाग लेने वाले 200 गुरुजी को सम्मानित किया गया। इस दौरान भागवत ने कहा, ''बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं, और उनके बुरे काम जारी हैं। बांग्लादेश पहला मामला नहीं है। पहला मामला अमेरिका का है।

संघ प्रमुख ने कहा कि मैंने एक अमेरिकी राइटर की लिखी किताब पढ़ी जिसका टाइटल है 'कल्चरल डेव

जन हितैषी

भारत में कॉर्पोरेट युद्ध चरम पर, नहीं चलेगी सरकार और सेबी की दादागिरी

भारत के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कॉर्पोरेट घरानों के बीच संघर्ष तेज़ हो गया है। भारत में कुछ विशिष्ट उद्योगपतियों को सरकार और सेबी द्वारा पिछले कई वर्षों से विशेष लाभ दिया जा रहा था। यह स्थिति क्रोनी पूंजीवाद (राजनीतिक संबंधों और प्रभाव का उपयोग कर एकाधिकार बनाने) का बड़ा उदाहरण है। सरकार कुछ चुनिंदा व्यवसायिक घरानों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नियम और कानून बनाकर समर्थन दे रही थी। भारत में नियामक संस्था सेबी द्वारा भी क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। ताज़ा उदाहरण अडानी समूह के साथ जुड़े कई विवादित मामलों में देखा जा सकता है। इस व्यवस्था के कारण देश के अन्य बड़े कारोबारी घरानों के बीच मे पिछले कई वर्षों से असंतोष बना हुआ था। भारत के कुछ विशिष्ट उद्योगपतियों को छोड़कर अन्य उद्योगपतियों को समान अवसर नहीं मिल रहे थे। सरकार और सेबी की सरपरस्ती के कारण अन्य उद्योगपतियों में डर का वातावरण बनाया गया था। वहीं अडानी-अंबानी जैसे कुछ घरानों को आर्थिक रूप से सतत लाभान्वित किया जा रहा था। इससे भारत के व्यापार जगत में भारी असंतुलन पैदा हो गया है। सरकारी नीतियों और निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव और पक्षपात के कारण अन्य उद्योगपति और कारोबारी समूह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को ही सरकार और सेबी के नियमों के माध्यम से विशेष लाभ मिलने के कारण भारत के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। सेबी और अन्य सरकारी संस्थानों के खिलाफ पक्षपात को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता के समीकरणों से जो आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा था, उसके खिलाफ अब सभी कारोबारी एकजुट होना शुरू हो गए हैं। ज़ी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्र ने जिस तरह के आरोप सेबी प्रमुख पर लगाए हैं, उसके बाद तो कॉरपोरेट जगत का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। भारत का व्यापारिक वातावरण निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बने। इसके लिए अब खुलकर भारतीय उद्योगपति सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सेबी के 500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर गड़बड़ियाँ उजागर करने में लग गए हैं। कई माह पहले हिंडनवर्ग की जो रिपोर्ट आई थी। भारत सरकार और सेबी ने उसे शार्टसेलर बताकर आरोपों को झुठला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच करने के आदेश दिए थे। वह जाँच भी सेबी के द्वारा कराई जा रही थी। जिसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद अब जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद भारतीय कॉरपोरेट जगत ने अपनी प्रतिक्रिया खुलकर देना शुरू कर दी है। सेबी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वित्त मंत्रालय को जो पत्र लिखा है। उस पत्र के सार्वजनिक होने तथा माधवी बुच के खिलाफ जो दस्तावेजी सबूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा सार्वजनिक किए गए हैं, उसके बाद इस तरह के घोटाले को दबाना संभव सरकार के लिए भी नहीं रहा। यह माना जा रहा है, कि सेबी प्रमुख माधवी बुच के पास इस्तीफा देने के अलावा अब अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका असर वर्तमान केंद्र सरकार पर पड़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला अभी लंबित है जिस तरह की परिस्थितियाँ बनने लगी हैं। उसके बाद अब यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जल्द ही इसके सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

अमेरिकी स्वपन का अंत निकट तो नहीं

अमेरिका विश्व के लगभग समस्त देशों पर अपनी चौधराहट सफलतापूर्वक लागू करता रहा है। पूरे विश्व में, एक तरह से लगभग समस्त क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रभावित करने में अमेरिका सफल रहा है एवं इस प्रकार अपनी प्रसारवादी नीतियों को भी लागू करता रहा है। परंतु, हाल ही के वर्षों में अमेरिका की आंतरिक स्थिति, लगभग समस्त क्षेत्रों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आदि, में लगातार बिगड़ती जा रही है। अमेरिका सहित विकसित देशों की, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में, आंतरिक स्थिति को देखते हुए अब तो पश्चिमी सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में आर्थिक विपन्नता एवं परिवार तथा समाज के खंड खंड होने के बाद पश्चिमी सभ्यता को पतित सभ्यता कहा जाने लगा है और इसे अब अमेरिकी स्वपन के अंत की शुरुआत भी माना जाने लगा है। अमेरिका में तो राष्ट्रीय ऋण 35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। इसका आशय यह है कि आय की तुलना में ऋण अधिक ले लिया गया है। अमेरिकी वित्त व्यवस्था पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि अमेरिकी सरकार को अपने सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी बाजार से और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस उद्देश्य से प्रति वर्ष अमेरिकी संसद में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पहुंचना होता है। यह स्थिति है विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका की।

वर्ष 1776 में जब पूंजीवाद के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने अपनी कृति ''द वेल्थ आफ नेशनस'' नामक किताब जारी की थी उस समय पूंजीवाद अपने शैशावस्था में ही था। उनका महत्वपूर्ण मुख्य सिद्धांत था कि व्यवसायी, जो अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय को बहुत ही कुशलता के साथ चलाना चाहते हैं। इस तरह ये व्यवसायी न केवल अपने आप को धनाडय बनाएंगे बल्कि वह देश इन धनाडयों के संसाधनों को जोड़कर स्वयं भी एक धनी देश बन जाएगा। पूरी 19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी में अमेरिका इसी सिद्धांत पर कार्य करता रहा है एवं अपने देश में धनाडयों की संख्या में अपार वृद्धि करता रहा है। इससे अमेरिकी नागरिकों में व्यक्तिवाद पनपा एवं वे परिवार एवं समाज के भले को भूलकर केवल अपने बारे में ही सोचने लगे एवं अपने व्यापार को पूरे विश्व में फैलाने लगे। इससे अमेरिका में गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही।

अमेरिका की 1940 के दशक में पूरे विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो गई थी, परंतु अब यह घटकर 17 प्रतिशत से भी कम हो गई है। कई उद्योगों के मामले में उत्पादन का जो एकाधिकार अमेरिका के पास होता था वह एकाधिकार अब अन्य देशों के पास चला गया है। अमेरिकी कम्पनियों ने कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्चे की पूरी लागत स्वयं वहन करना प्रारम्भ किया था। अमेरिका में श्रम लागत भी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, अन्य देशों में श्रमिक, अमेरिकी श्रम लागत की तुलना में, आधी से भी कम राशि में ही काम करने को तैयार हो रहे थे। इस बीच अमेरिकी सरकार ने आय कर की दरें भी बढ़ाकर 35 प्रतिशत से अधिक कर दी थीं। जबकि अन्य देशों में आय कर की दरें 20/25 प्रतिशत थीं। इससे अमेरिका में विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ने लगी। अतः धीरे धीरे अमेरिका में विनिर्माण इकाईयां बंद होने लगीं। वर्ष 1979 में अमेरिका में 20 प्रतिशत श्रमिक विनिर्माण इकाईयों में कार्यरत थे अब यह संख्या घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है। अमेरिका में 2 करोड़ कर्मचारी विनिर्माण इकाईयों में कार्य कर रहे थे जो घटकर 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। अमेरिका में जब प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी उस समय 10 श्रमिकों में से 9 श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे (छोटे कृषक) जबकि आज केवल 2 प्रतिशत श्रमिक ही कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार अमेरिका में रोजगार की दृष्टि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में बहुत अधिक संकुचन हुआ है।

1950 के दशक से लेकर अमेरिका में स्टील उद्योग, कपड़ा उद्योग (वस्त्र, परिधान एवं टेक्सटाइल), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लगभग समाप्त से हो गए हैं। वाहन उद्योग के क्षेत्र की बड़ी बड़ी कम्पनियों ने अपनी विनिर्माण इकाईयां चीन आदि देशों में स्थापित की हैं। साथ ही, जापान की कई कम्पनियों ने वाहन के क्षेत्र में अमेरिका में आकर अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की है। इस प्रकार, कुल मिलाकर उक्त उद्योगों में अमेरिकी मूल के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए हैं अथवा बिलकुल ही समाप्त हो गए हैं। अमेरिका में उपयोग हो रहे स्मार्ट सेल फोन के 50 प्रतिशत से अधिक उपकरण आयात किए जा रहे हैं एवं इनका उत्पादन अमेरिका में नहीं हो रहा है।

ब्यूरो आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स - मासिक लेबर रिव्यू दिसम्बर 2016 के अनुसार, अमेरिका में प्रति घंटा वास्तविक मजदूरी दर - वर्ष 1947 में 5.35 अमेरिकी डॉलर थी जो वर्ष 1973 में बढ़कर 9.26 अमेरिकी डॉलर हो गई। परंतु, उसके बाद से लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है जो वर्ष 2015 में 9.07 अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष 1947 से 1973 के बीच प्रति घंटा वास्तविक मजदूरी दर 73 प्रतिशत से बढ़ी थी जबकि इसी दौरान उत्पादकता में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं वर्ष 1973 से 2015 के बीच प्रति घंटा वास्तविक मजदूरी दर 3 प्रतिशत कम हुई है और उत्पादकता 109 प्रतिशत बढ़ी है। इस बीच रोजगार के नए अधिकतम अवसर उच्च मजदूरी वाले क्षेत्रों से घटकर कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में बढ़े हैं। जैसे विनिर्माण इकाईयों के बंद होने से भारी संख्या में श्रमिक वर्ग को सेवा क्षेत्र में कम मजदूरी के रोजगार स्वीकार करने पड़े है। वर्ष 1979 के बाद से 40 प्रतिशत से अधिक रोजगार के अवसर विनिर्माण क्षेत्र में कम हुए हैं। साथ ही, तकनीकी विकास ने भी उत्पादकता तो बढ़ाई है परंतु मजदूरी की दरें नहीं बढ़ पाई हैं।

अमेरिका में समय के साथ साथ विनिर्माण इकाईयां बंद होती गईं एवं उच्च तकनीकी, सूचना आधारित सेवा क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में, रोजगार के अधिक अवसर उभरते गए। अब तो बहिःस्त्रोतन (आउट्सॉर्सिंग) के चलते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। अतः अमेरिका में आने वाले समय में विनिर्माण इकाईयों के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है।

उक्त कारणों के चलते अमेरिका में गरीबी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबी के चलते इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, यह वर्ग बहुत ही तंग हालत में रहता है एवं अंततः सामाजिक अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। इनके मकानों में बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अमेरिका में गरीबी रेखा का निर्धारण अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। वर्ष 2015 में गरीबी आंकलन के लिए प्रत्येक चार व्यक्तियों के परिवार के लिए प्रतिवर्ष 24,300 अमेरिकी डॉलर की आय तय की गई थी। इससे कम आय वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। आय की उक्त गणना के आधार पर अमेरिका में 13.5 प्रतिशत परिवार (4.31 करोड़ अमेरिकी नागरिक) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे।

गरीब वर्ग के नागरिकों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के चलते अमेरिका में 22 लाख अमेरिकी गरीब नागरिक जेलों में बंद थे एवं 50 लाख गरीब नागरिक पैरोल अथवा परीक्षण पर थे एवं अन्य 10 लाख नागरिक जो जेलों से छूट गए थे, वे न तो पेरोल पर थे और न ही परीक्षण पर थे, परंतु वे कभी भी पुनः जेलों में भेजे जा सकते हैं।

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नागरिकों के अतिरिक्त 20 लाख से 30 लाख नागरिक ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है जिन्हें यहां ''होमलेस'' कहा जाता है। 50 लाख अमेरिकी नागरिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एवं 80 लाख नागरिक सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग योजना का लाभ ले रहे हैं।

एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका में तीन से साढ़े तीन करोड़ नागरिक स्थायी निम्नवर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो अमेरिका की कुल 32.5 करोड़ जनसंख्या का 10 प्रतिशत है। प्रत्येक 5 अमेरिकी बच्चों में से एक बच्चा गरीब वर्ग का है। इतना अधिक खर्च करने के बाद भी अमेरिका में सामाजिक सहायता व्यवस्था अन्य अमीर एवं विकसित देशों की तुलना में कमतर ही मानी जाती है। करोड़ों अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिक केयर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि यह सुविधा उपलब्ध भी है तो चार में से केवल एक नागरिक को ही डॉक्टर से उसी दिन का मिलने का समय मिल पाता है।

अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में इस प्रकार के हालात देख कर अब तो कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के पूंजीवादी मॉडल पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया जाने लगा है एवं यह कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिकी स्वपन का अंत निकट तो नहीं है। (लेखक - प्रहलाद सबनानी/ईएमएस) (सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक)

जद(यू) को संजीवनी देगी बीजेपी

बिहार में जद(यू) अगले विधानसभा चुनाव तक पुरी मजबूती से टिके रहेगी इसका कारण यह है की बिहार का राजनीति समीकरण ऐसा है कि वहाँ मुख्य रूप से तीन पार्टी है जो इस प्रकार है बीजेपी, आरजेडी व जद (यू) जब भी क़ोई दो पार्टी मिलती है तभी सरकार बनती है वहाँ का जातियों का समीकरण ही कुछ इसी तरह का है बीच में लोजपा भी है और जो दो गुटों में है वो भी इधर मजबूत हो रही है और खासकर लोजपा (रामविलास) के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है क्योंकि वहाँ जीत का मार्जिन बहुत ही कम वोटो के अंतर से होता है और बीजेपी 2015 के विधानसभा में अपने कुछ छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों के सहारे केवल 55सीट पर सिमट गई थी और जद (यू) व आरजेडी को 71 व 80सीट मिले थे बिहार के मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से समझना किसी के बस की बात नहीं है यदि कहीं वो फिर से पाला बदलेंगे तो बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि आज भी मुख्य मंत्री नीतीश कुमार का अच्छा जनाधार है एक बार जब जद (यू) व आरजेडी का गठबंधन बना था तो मैं रिक्शा से रिक्शावाला से पूछा कि क्या भाई आप किस को वोट दे रहें हैं कहा देना तो था लालूजी को लेकिन जब गठबंधन बना है तो जद (यू) को ही सब मिलकर वोट करेंगे अतः जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में हैं तो ऐसे में बीजेपी क़ोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी वहाँ अभी भी बाहुबली का राज है तभी तो लोकसभा में जेल से पेरोल पर चुनाव में बुलाया गया और बीजेपी भी जद (यू) को तोड़ने का क़ोई प्रयास नहीं करेगी क्योंकि अगर उसे तोड़ दी तो उसी का नुकसान हो सकता है क्योंकि बाहुबली सब आरजेडी या निर्दलीय चुनाव लड़ कर एक अच्छा वोट बैंक ला सकती है नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर हैं इसलिए इन सब बदलाव पर कुछ बोल नहीं रहें है लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें भी पार्टी के बारे में मालूम हो रहा होगा चूंकि केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है और सरकार एनडीए की है अतः क़ोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी क्योंकि श्री नीतीश कुमार जब सारा विपक्ष को एक कर दी थी ऐ सही बात है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने उन्हें भाव नहीं दिया और पाला बदलकर पुनः एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार को जब लगा कहीं जद(यू) में टूट होकर कहीं पीएम के चक्कर में सीएम की कुर्सी भी तेजस्वी को ना चला जाए तो प्रधानमंत्री मोदीजी के पास अन्य लोगों के माध्यम से लोकसभा चुनाव हेतु लगा कि जद (यू) की सीट आरजेडी और कॉंग्रेस व अन्य के साथ गठबंधन से 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा और ऐसे में जद(यू) का वजूद ना ख़त्म हो जाए तभी बीजेपी को भी लगा अकेले अधिक सीट मिलना मुश्किल है तो एनडीए में जद(यू) प्रधान मंत्री श्री मोदीजी के कहने पर ही शामिल हो गई और उसे सम्मानजनक सीट मिला और आरजेडी देखते रह गई और एनडीए ने चिराग और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मिलकर चुनाव लड़े और बिहार के 35 सीट में से एनडीए को बिहार में 40 सांसदों के चुनाव में । बीजेपी, 17, जद (यू), 16, .एलजेपी, 6 हम 1सीट, आरएलएम यानि एन डी ए ने कुल 40 सीट पर उम्मीदवार उतारा और जिसमें से बीजेपी, 12 जद (यू), 12, .एलजेपी, 5 और हम 1सीट यानि कुल 30 सीट झटक लिए जिसमें जद यू को 16 में से 12सीट मिला कुछ सीटों पर बहुत टफ फाइट था कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहाँ जद (यू) सीट लेती है अतः नीतीश कुमार जब तक हैं पार्टी आराम से चलेगी क्योंकि बीजेपी में स्व सुशील मोदी जैसा क़ोई चेहरा नहीं जो सीट ले सके और जनाधार नीतीश कुमार जैसा नहीं है जंगलराज से बिहार को बाहर लाने में जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला है वैसे में जद(यू) के अस्तित्व पर फिलहाल क़ोई खतरा नहीं दिख रहा है अब जब पुल के बारे में एनडीए में बीजेपी कुछ नहीं बोलती है तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ के सी त्यागी को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए ख़ासकर उससमय जब चुनाव परिणाम के बाद सब की धड़कन रूकी थी तभी उनका बयान आता है कि श्री नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था और तभी तेजस्वी यादव उसका मज़ाक उड़ाते नजर आते हैं ऐसे में पार्टी के अंदर लगता है अनर्थ हो रहा है अब जब श्री ललन सिंह जद यू के कैबिनेट मंत्री बन गए और विपक्ष का संसद में मुँह बन्द कर देते हैं वैसा तालमेल की कमी पार्टी को लगी होगी और फिर अग्निवीर और जातीय जनगणना पर बेबजह बोलने लगते हैं तो विरोधाभास होने लगता है जंगल त्याग ख़त्म तो बिहार से लगभग ख़त्म हो गया लेकिन बाहुबली का दबदबा अभी भी बिहार में है ऐसे में बीजेपी टिकट देकर अपनी छवि ख़राब नहीं करना चाहेगी और बिहार में जब ढेरों परियोजना का एनडीए द्वारा शुभारम्भ हुआ है तो सत्ता भी नहीं जाने देगी औ- जद(यू) को संजीवनी देकर एनडीए सरकार को बनाए रखना चाहेगी ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो औ- रोजगार मिल सके।बिहार में जद(यू) अगले विधानसभा चुनाव तक पुरी मजबूती से टिके रहेगी इसका कारण यह है की बिहार का राजनीति समीकरण ऐसा है कि वहाँ मुख्य रूप से तीन पार्टी है जो इस प्रकार है बीजेपी, आरजेडी व जद (यू) जब भी क़ोई दो पार्टी मिलती है तभी सरकार बनती है वहाँ का जातियों का समीकरण ही कुछ इसी तरह का है बीच में लोजपा भी है और जो दो गुटों में है वो भी इधर मजबूत हो रही है और खासकर लोजपा (रामविलास) के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है क्योंकि वहाँ जीत का मार्जिन बहुत ही कम वोटो के अंतर से होता है और बीजेपी 2015 के विधानसभा में अपने कुछ छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों के सहारे केवल 55सीट पर सिमट गई थी और जद (यू) व आरजेडी को 71 व 80सीट मिले थे बिहार के मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से समझना किसी के बस की बात नहीं है यदि कहीं वो फिर से पाला बदलेंगे तो बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि आज भी मुख्य मंत्री नीतीश कुमार का अच्छा जनाधार है एक बार जब जद (यू) व आरजेडी का गठबंधन बना था तो मैं रिक्शा से रिक्शावाला से पूछा कि क्या भाई आप किस को वोट दे रहें हैं कहा देना तो था लालूजी को लेकिन जब गठबंधन बना है तो जद (यू) को ही सब मिलकर वोट करेंगे अतः जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में हैं तो ऐसे में बीजेपी क़ोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी वहाँ अभी भी बाहुबली का राज है तभी तो लोकसभा में जेल से पेरोल पर चुनाव में बुलाया गया और बीजेपी भी जद (यू) को तोड़ने का क़ोई प्रयास नहीं करेगी क्योंकि अगर उसे तोड़ दी तो उसी का नुकसान हो सकता है क्योंकि बाहुबली सब आरजेडी या निर्दलीय चुनाव लड़ कर एक अच्छा वोट बैंक ला सकती है नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर हैं इसलिए इन सब बदलाव पर कुछ बोल नहीं रहें है लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें भी पार्टी के बारे में मालूम हो रहा होगा चूंकि केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है और सरकार एनडीए की है अतः क़ोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी क्योंकि श्री नीतीश कुमार जब सारा विपक्ष को एक कर दी थी ऐ सही बात है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने उन्हें भाव नहीं दिया और पाला बदलकर पुनः एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार को जब लगा कहीं जद(यू) में टूट होकर कहीं पीएम के चक्कर में सीएम की कुर्सी भी तेजस्वी को ना चला जाए तो प्रधानमंत्री मोदीजी के पास अन्य लोगों के माध्यम से लोकसभा चुनाव हेतु लगा कि जद (यू) की सीट आरजेडी और कॉंग्रेस व अन्य के साथ गठबंधन से 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा और ऐसे में जद(यू) का वजूद ना ख़त्म हो जाए तभी बीजेपी को भी लगा अकेले अधिक सीट मिलना मुश्किल है तो एनडीए में जद(यू) प्रधान मंत्री श्री मोदीजी के कहने पर ही शामिल हो गई और उसे सम्मानजनक सीट मिला और आरजेडी देखते रह गई और एनडीए ने चिराग और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मिलकर चुनाव लड़े और बिहार के 35 सीट में से एनडीए को बिहार में 40 सांसदों के चुनाव में । बीजेपी, 17, जद (यू), 16, .एलजेपी, 6 हम 1सीट,आरएलएम यानि एन डी ए ने कुल 40 सीट पर उम्मीदवार उतारा और जिसमें से बीजेपी, 12 जद (यू), 12, .एलजेपी, 5 और हम 1सीट यानि कुल 30 सीट झटक लिए जिसमें जद यू को 16 में से 12सीट मिला कुछ सीटों पर बहुत टफ फाइट था कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहाँ जद (यू) सीट लेती है अतः नीतीश कुमार जब तक हैं पार्टी आराम से चलेगी क्योंकि बीजेपी में स्व सुशील मोदी जैसा क़ोई चेहरा नहीं जो सीट ले सके और जनाधार नीतीश कुमार जैसा नहीं है जंगलराज से बिहार को बाहर लाने में जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला है वैसे में जद(यू) के अस्तित्व पर फिलहाल क़ोई खतरा नहीं दिख रहा है अब जब पुल के बारे में एनडीए में बीजेपी कुछ नहीं बोलती है तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ के सी त्यागी को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए ख़ासकर उससमय जब चुनाव परिणाम के बाद सब की धड़कन रूकी थी तभी उनका बयान आता है कि श्री नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था और तभी तेजस्वी यादव उसका मज़ाक उड़ाते नजर आते हैं ऐसे में पार्टी के अंदर लगता है अनर्थ हो रहा है अब जब श्री ललन सिंह जद यू के कैबिनेट मंत्री बन गए और विपक्ष का संसद में मुँह बन्द कर देते हैं वैसा तालमेल की कमी पार्टी को लगी होगी और फिर अग्निवीर और जातीय जनगणना पर बेबजह बोलने लगते हैं तो विरोधाभास होने लगता है जंगल त्याग ख़त्म तो बिहार से लगभग ख़त्म हो गया लेकिन बाहुबली का दबदबा अभी भी बिहार में है ऐसे में बीजेपी टिकट देकर अपनी छवि ख़राब नहीं करना चाहेगी और बिहार में जब ढेरों परियोजना का एनडीए द्वारा शुभारम्भ हुआ है तो सत्ता भी नहीं जाने देगी औ- जद(यू) को संजीवनी देकर एनडीए सरकार को बनाए रखना चाहेगी ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो औ- रोजगार मिल सके और श्री लालू यादव का दबदबा खत्म हो क्योंकि चुनाव में प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का ऐसा इस्तेमाल हुआ कि मोदी का परिवार लगाना पड़ा। (लेखक-संजय गोस्वामी/ईएमएस)

बुलडोजर नीति विरुद्ध न्यायिक पहल

बुलडोजर नीति से सुराज मंडित सरकारों के भ्रम पर आखिरकार शीर्ष न्यायालय का अंकुश लग गया । जस्टिसद्व्य वी आर गवई व के वी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया कि दोषियों को उनके निकेत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक स्वस्थ लोकतंत्र में अपराध के मर्म और प्रकृति को जाने बिना मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति के संपूर्ण परिवार को उसकी छाया से बेदखल कर असुरक्षित जीवन जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

दरअसल अपराध का मार्ग सत्ता के आचरण से उत्पन्न होता है। जब आम आदमी को भरण पोषण के सतही विकल्पों से वंचित कर वीआईपी संस्कृति वाली अपराध की दुनिया में लिप्त लोगों को आदर्श बताते हुए सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं तो अपराध कैसे रुकेंगे। ऐसा करने के पीछे अडानी अंबानी जैसे लोगों को उपकृत करना है जो सत्ता प्राप्त की वित्तपोषक है।

अवांछित विज्ञापन चलचित्र धर्म प्रदर्शन, भीड़ तंत्र और मीडिया इसकी हवि है जो अपराध तंत्र की पनाहगार है ,जो लोगों के धैर्य और विवेक का क्षरण करते हुए निरपराध और अपराध के अंतर को पाटते है जिसे हम भागलपुर कांड में पुलिस और बिलकिस बानो के दोषियों के महिमा मंडन में देख सकते हैं देश में पुलिस प्रशासन और अपराधियों की मिलीभगत चहुंओर बयान हो रही है । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर न्याय की कथित लोकप्रियता का प्रभाव राजस्थान,असम, महाराष्ट्र , दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों पर पड़ा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के मद्देनजर खरगोन मेंअप्रैल 2022 में हुए सांप्रदायिक झड़पों के बाद बुलडोजर नीति का दुरूपयोग किया। उनकी सरकार ने 16 घर और 29 ढाँचे ध्वस्त कर दिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब उद्देश्य शुभ न हो तो ज्ञान पाप हो जाता है। इसकी बानगी हम देख ही रहे हैं। लेकिन

मध्यप्रदेश के इतिहास में एक दौर ऐसा भी रहा है जब बुलडोजर नीति का सदुपयोग सार्वजनिक विकास के लिए किया गया। इन सबसे पहले मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल वर्ष 1990-92 में नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को समर्पित है। नए भोपाल के बुनियादी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उन्हें बुलडोजर मैन के रूप में याद किया जाता है।

उस दौरान गौर ने राज्य में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य शहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। सुलभ यातायात के लिए उन्होंने भोपाल की प्रसिद्ध वीआईपी रोड सहित भारत टॉकीज के आसपास के क्षेत्र में बांधा बनी इमारतों को ध्वस्त किया और स्थानीय निवासियों और राजनीतिक नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद रेलवे स्टेशन पर यातायात व्यवस्था बहाल की। आपराधिक मामलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया शिनाख्त सदन में पारित हो चुका है जिसमें अपराधियों के जैविक और शारीरिक नमूने लिए जा सकेंगे। देखना है कि हांगकांग की तरह सरकार अपने दोष छुपाने के लिए कानून का दुरुपयोग करती है या सुशासन लाने की दिशा में अपराध प्रवृत्ति के निर्मूलन में इसका उपयोग। (लेखक- राकेश कुमार वर्मा/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8120

बाएँ से दाएँ

1.सुगंध,खुशबू-3
3.व्यवस्था-2,2
5.आम लोग-2
6.चिंतन,सोच विचार-3
7.पराया-2
8.विनाश,विध्वंस-2
10.अपने ही घर में बंधक-5
12.वसव,घेरा-3
15.आंचल,पल्लू-3
17.सेंधमार-5
20.भाग्य (अंग्रेजी-2)
22.एक सवारी गाड़ी-2
23.पीहर,पिता का घर-3
24.नवीन,नया,नवजात-2
25.लात मारना-4
26.जोंक,न भरने वाला जख्म-3

ऊपर से नीचे

1.जी,चित्त,इच्छा-2
2.करधनी,कमर में पहना जाने वाला आभूषण-5
3.तार कसना-3
4.जोकर,विदुषक-4
5.दुनिया,जगत-3
7.पेख-2
9.सदैव,हरदम-2
11.जन्म,पैदा होना-3
13.जुड़वा-3
14.आश्चर्य में पड़ना-5
15.जंगल की आग-4
16.टोंटी,नलका-2
18.वश,अधीन-2
19.परिणाम,हल-3
21.अर्जित करना-3
24.लोहे की तांत-2

शब्द पहेली -8119 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का प्रदर्शन ओलंपिक दल से भी बेहतर रहा

सरकार से मिले सहयोग की भी रही अहम भूमिका

पेरिस (ईएमएस)। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय पैरालंपिक दल का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय पैरालंपिक दल ने अब तक 15 पदक पदक जीत लिये हैं जबकि अभी चार दिन और खेल होने हैं। भारतीय दल में 32 महिला खिलाड़ी भी शामिल रही हैं। सरकार ने पैरालंपिक दल को भी ओलंपिक दल की तरह ही सुविधाएं दी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भी दल के सदस्यों का हौंसला बढ़ाया और उन्हें जीत पर बधाई दी। भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तर का प्रशिक्षण और विदेशी कोच की भी सेवाएं उपलब्ध करायी गयीं। भारतीय पैरालंपिक दल दल का प्रदर्शन ओलंपिक दल से कहीं बेहतर रहा है।

सरकार ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उप

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 151 , निफ्टी 53 अंक नीचे आया

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को भी गिरावट पर बंद हुए। वहीं गत दिवस भी बाजार में गिरावट रही है। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। आज बाजार में आज वाहन और संपत्ति शेयरों में भारी गिरावट रही । दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 151.48 करीब 0.18 फीसदी नीचे आकर 82,201.16 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53.60 अंक तकरीबन 0.21 फीसदी नीचे आकर 25,145.10 के स्तर पर बंद हुए।

सेंसेक्स के कुल 10 शेयर ही आज लाभ के साथ ही ऊपर आये जबकि निफ्टी के 17 शेयर बढ़त पर साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी ऑटो, ऑयल एंड गैस और रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली। आज निफ्टी रियल्टी 0.97फीसदी निफ्टी ऑटो 0.38फीसदी और ऑयल एंड गैस 0.38 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। व्यापक स्तर पर देखा जाए तो स्मॉल और मिड-कैप क्रमश 1 फीसदी और 0.4 फीसदी बढ़कर शीर्ष स्तर पर पहुंचे।

एशियाई शेयर बाजार आज नीचे आया। जापानी शेयर तीन सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर खिसक गये। बाजार जानकारों के अनुसार निवेशकों को अमेरिकी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें है और इसका प्रभाव भी बाजार पर पड़ा है।

आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में सबसे अधिक लाभ वाले शेर टाटा समूह की कंपनी टाइटन के रहे। टाइटन के शेयर बीएसई पर 3.11 फीसदी बढ़कर 3721.40 रुपये पर जबकि एचिपर 3.11 फीसदी की बढ़त के साथ 3,720 रुपये पर बंद हुए। इसके अलावा, निफ्टी पर सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों में एलटीआई माइंडट्री , विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसीस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, इंफोसिस, एचसीएल टेक, हिंडाल्को और टीसीएस के शेयर रहे।

वहीं नुकसान वाले शेयरों में निफ्टी के 33 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जिनमें कोका-कोला इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सिप्ला, डॉ. रेड्डीज लैब्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.46 फीसदी तक गिरे।

बीएसई के रिलायंस इंडस्ट्रीज , टाटा मोटर्स, नेस्ले इंडिया और भारती एयरटेल सहित 20शेयर लाल निशान में बंद हुए, इसमें 1.41फीसदी तक की गिरावट रही।

वहीं इससे पहले आज सुबह

बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 82,474 पर खुला जबकि निफ्टी 51 अंक ऊपर 25,250 पर खुला। इसके अलावा 13 प्रमुख सेक्टर में से ग्यारह हरे निशान में चल रहे थे जबकि घरेलू स्तर पर केंद्रित स्माल और मिड कैप में लगभग 0.5 फीसदी की वृद्धि देखी गई।अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने मंदी की चिंताओं को एक बार फिर जन्म दे दिया है और इसका पिछले सत्र में वैश्विक बाजारों पर असर पड़ा।

सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल

- सोने का भाव 71,500 रुपए, चांदी 83,700 रुपए के करीब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने-चांदी के वायदा कारोबार के शुरुआत में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 71,500 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 83,700 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 15 रुपये की तेजी के साथ 71,481 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 23 रुपये की तेजी के साथ 71,489 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 37 रुपये की तेजी के साथ 83,602 रुपये पर खुला। इस समय यह 137 रुपये की तेजी के साथ 83,702 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,526.39 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,526 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 2.40 डॉलर की तेजी के साथ 2,528.40 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 28.63 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 28.55 डॉलर था। इस समय यह 0.14 डॉलर की तेजी के साथ 28.69 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी की नियुक्ति में विशेष रूचि दिखाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी की नियुक्ति में विशेष रूचि दिखाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों के प्रमुखों से 'पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम सामंती युग में नहीं हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए एक आईएफएस अधिकारी को 'राजाजी टाइगर रिजर्व' का निदेशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े किए।

न्यायालय ने कहा कि प्रथम अधिकारी की ओर से एक विशेष नोटिंग की गई थी कि राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे उप सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के वन मंत्री ने भी मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा, 'इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो भी कहा है, वही करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा, 'हम सामंती युग में नहीं हैं।

पीठ ने पूछा, 'मुख्यमंत्री को उनसे (अधिकारी से) विशेष स्नेह क्यों होना चाहिए? शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, 'सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, क्या वह कुछ भी कर सकते हैं? इसने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है। 'नोटिंग' में की गई इस टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए कि अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री बस इसे अनदेखा कर रहे हैं।

न्यायालय ने कहा, 'यदि आप डेस्क अधिकारी, उप-सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री से असहमत हैं, तो कम से कम यह तो अपेक्षित है ही कि इस बात पर विचार किया जाए कि वे लोग प्रस्ताव से असहमत क्यों हैं। न्यायालय ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने सभी की सलाह के खिलाफ काम किया है। पीठ ने कहा, 'जब तक उन्हें विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त नहीं किया जाता, आप उन्हें अच्छे अधिकारी का प्रमाणपत्र नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के वन मंत्री और मुख्य सचिव ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।

हालांकि, राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि भारतीय वन सेवा अधिकारी को इस अभयारण्य का निदेशक नियुक्त करने का आदेश तीन सितंबर को वापस ले लिया गया है।

सेबी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए सख्त नियम लाएगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए जल्द ही सख्त नियम अधिसूचित करने पर ?विचार कर रहा है। बाजार नियामक के इस कदम का उद्देश्य अटकलबाजी वाली ट्रेडिंग गतिविधियों को काबू में करना है क्योंकि इससे हर साल खुदरा निवेशकों को कुल 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगती है। उद्योग के भागीदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर बाजार नियामक ने जुलाई में जारी परामर्श पत्र में सात उपाय प्रस्तावित किए थे। मामले के जानकार ने कहा कि सेबी की आगामी बोर्ड बैठक में इसे मामूली बदलाव के साथ लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार नियामक के पास प्रस्तावों को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही अंतिम मानदंड जारी करने का भी प्रावधान है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नियामक उन खुदरा निवेशकों के हित में जल्द से जल्द सुरक्षा तंत्र कायम करना चाहता है जो अक्सर इस क्षेत्र में अपना पैसा गंवाते रहते हैं। इस बारे में पुष्टि के लिए सेबी को ईमेल किया गया मगर खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। सेबी के परामर्श पत्र पर 20 अगस्त की समयसीमा तक आम लोगों और प्रमुख हितधारकों सहित 6,000 से अधिक इकाइयों की प्रतिक्रियाएं आईं। सेबी को उपायों का चरणबद्ध तरीके से लागू करना, ट्रेडरों के लिए योग्यता की शर्तें लगाना मानदंड और उच्च मार्जिन आवश्यकता तथा पोजीशन लिमिट से संबंधित नियमों को थोड़ा आसान बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। सेबी के प्रमुख प्रस्तावों में साप्ताहिक ऑप्शन अनुबंधों को प्रति एक्सचेंज एक सूचकांक तक सीमित करना, सौदे के निपटान के करीब उच्च मार्जिन की आवश्यकता तथा अनुबंध के आकार को बढ़ाना शामिल हैं। इसके साथ ही नियामक ने न्यूनतम अनुबंध आकार को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15-20 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया है। अनुबंध शुरू होने के छह महीने बाद इसे और बढ़ाया जा सकता है।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म, इंतजार अब दिसंबर का

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा खत्म हो चुकी है। सभी अभिर्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में हिस्सा ले लिया है... अब इंतजार हो रहा हैं सिर्फ रिजल्ट का।

बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस भर्ती प्रकिया को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देकर संपन्न कराने में जुटी है। खबरों के मुताबिक दिसंबर तक इस परीक्षा के नतीजे आ सकते हैं। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि जहां दिसंबर में परीक्षा के नजीते आ जाएंगे वहीं जनवरी महीने में शारीरिक टेस्ट होगा। उसके बाद सीधे नौकरी अभिर्यर्थियों को मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय लग सकता है।

बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अधिकारियों के साथ पूरी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई है। खबरों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर अभ्यार्थियों के आपत्ति पत्र मंगाने शुरू हो जाएंगे, इसके साथ ही बोर्ड को परीक्षा में शामिल हुए अभ्यार्थियों की दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। वहीं परीक्षा के दौरान जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेज का मिलान नहीं हो पाया था... उसका भी परीक्षण होना है।

बताया जा रहा है कि सभी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अगले चरण में मैरिट लिस्ट जारी होगी। माना जा रहा है कि दिसंबर महीने के अंत तक तैयार होगी और परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं इसके बाद नतीजे आने के बाद जनवरी माह में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यार्थियों को जहां 4.8 किमी की दौड़ और महिला अभ्यार्थियों को 2.4 की दौड़ कराई जाएगी। इसके लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

एक बार पेपर लीक होने के बाद दोबारा हुई है परीक्षा

बता दें कि यूपी पुलिस में 60 हजार 244 रिक्त पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले महीने अगस्त में 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख़ को हुआ था। ये परीक्षा दो पालियों में कराई गई थी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, वहीं योगी सरकार ने इस परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराने के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके बाद अभी तक किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। बता दें कि ये परीक्षा फरवरी महीने में पेपर लीक हो जाने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी।

मस्जिद के कथित अवैध निर्माण पर विवाद....हिंदु संगठनों ने दो दिन दिए

ओवैसी का तंज, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत

शिमला (ईएमएस)। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर न केवल स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया।

राज्य के कई मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माणपरअपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बड़ी बात ये है कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा में मुद्दे पर जिस बेबाकी से स्टैंड लिया, उनके समर्थन में सत्ता पक्ष से अधिक विपक्ष दिखाई दिया। अवैध निर्माण के मामले से हिमाचल प्रदेश सड़क से लेकर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। गुरुवारको हिंदू संगठनों के लोग दोपहर बाद एकत्र हुए और रोष मार्च निकाला। उधर हिमाचल विधानसभा में मुद्दे पर सरकारी रिपोर्ट रखने वाले मंत्री सिंह भी यहां पर पहुंचे और धरना के संबोधित किया। वहीं हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है।

वहीं ओवैसी ने हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है।

वहीं, सिंह ने ओवैसी के बयान पर जवाब देकर कहा कि, मंदिर-मस्जिद निजी संपत्ति नहीं हैं। यहां वैध और अवैध का मामला है। अवैध तब अवैध है। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। उनकी राजनीति केवल एक समुदाय के दम पर चलती है। उन्होंने दावा किया कि अपराधिक पृष्टभूमि के लोग हिमाचल आ रहे हैं। वहीं मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किन कारणों के चलते ऐसी स्थिति उपजी उसकी जांच हो रही है। प्रदेश में शांतिप्रिय प्रदर्शन का सम्मान होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

बाबा रामदेवरा में दर्शन करने उमड़ रही भक्तों की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

जोधपुर,(ईएमएस)। प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेवरा का मसूरिया मेला शुरू हो गया है। बाबा के दर्शन के लिए बुधवार रात से ही भक्तों यहां आना शुरू हो गया। तड़के 4:15 बजे भव्य मंगला आरती की गई। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। भक्तों को असुविधा न हो इसके लिए मेला स्थल पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया अब तक करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यहां से भक्त आगे रामदेवरा जा रहे हैं।

जोधपुर के एडिशनल एसपी निशांत भारद्वाज ने कहा कि बाबा रामदेवरा के मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते तीन शिफ्ट लगाई गई हैं। रात में भारी भीड़ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मसूरिया मंदिर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि जब बाबा रामदेव ने रूणेचा में समाधि ली थी तब कहा था कि मेरी समाधि पर आने से पहले जो मेरे गुरु की समाधि के दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना जरुरी पूरी होगी।

ड्रोन के सुरक्षित संचालन के लिए दिशानिर्देशों पर काम कर रहे हैं गृह मंत्रालय : नायडू

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि नागर विमानन और गृह मंत्रालय ड्रोन के सुरक्षित संचालन के साथ-साथ उसके उ?चित उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को लेकर काम कर रहे हैं। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार मणिपुर में हाल की घटना के संदर्भ में गलत मकसद से उड़ाए जा रहे ड्रोन के मामलों से निपटने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है। मणिपुर में हाल ही में जातीय हिंसा के दौरान उग्रवादियों ने बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। नायडू ने कहा ?कि ड्रोन को लेकर सुरक्षा का पहलू भी है।

हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ दिशानिर्देश तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों का मकसद सुरक्षित संचालन और ड्रोन का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठा रही है। नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी में एक सम्मेलन से इतर कहा ?कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न गतिविधियों, खासकर कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल का काफी समर्थन कर रहे हैं।

जब हम दिशानिर्देश तैयार करते हैं तो इसमें ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ सुरक्षा के पहलू को भी ध्यान में रखना होता है। यह एक अंतर-मंत्रालयी प्रयास होगा, हम विचार-विमर्श की प्रक्रिया में हैं।

मिजोरम में पेट्रोल-डीजल 4रुपए महंगा हुआ

नई दिल्ली (ईएमएस)। देशभर में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार ?गिरावट देखी जा रही हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में लंबे समय से पेट्रोल-डीजल के भाव भले ही एक ही लेवल पर बरकरार हों लेकिन अब मिजोरम सरकार ने दोनों की कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमत को महीने की शुरुआत से लागू कर दिया गया है। राज्य के एक मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। मिजोरम के कराधान मंत्री डॉ. वनललथलाना ने कहा कि ईंधन कीमत में यह बढ़ोतरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड मेंटीनेंस के लिए पैसा जुटाने के इरादे से की गई है।

उन्होंने कहा ?कि सरकार ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेस के लिए पेट्रोल-डीजल दोनों पर दो-दो रुपए लीटर और रोड मेंटीनेंस के लिए 2 रुपए लीटर का नया शुल्क लगाया है। वनललथलाना ने कहा कि नई कीमत राज्य में 1 एक सितंबर से लागू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के फायदे के लिये लिया गया है। वनललथलाना ने कहा कि 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और हाल में वैट शुल्क बढ़ाने के बावजूद पेट्रोल-डीजल का नया भाव साल 2021 की कीमत से कम है। मिजोरम सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर वैट 5.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और डीजल पर 16.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने के बाद राजधानी आइजोल में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 99.24 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 88.02 रुपए प्रति लीटर है। मंत्री की तरफ से बताया गया कि यह फैसला राज्य के रिसोर्स जुटाने वाली समिति की सिफारिश के अनुरूप लिया गया है। संबंधित समिति को राजस्व बढ़ाने के तरीके तलाशने का काम सौंपा गया था।

पुतिन यूक्रेन से बातचीत को तैयार लेकिन 2022 के समझौते पर

मास्को (ईएमएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन केवल उस समझौते के आधार पर जो 2022 में इस्तांबुल में रूस और कीव के वार्ताकारों के बीच तय हुआ था। पुतिन ने कहा, क्या हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं? हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन कुछ अस्थायी मांगों के आधार पर नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों के आधार पर जो इस्तांबुल में सहमत और प्रारंभ किए गए थे।

रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे सुरक्षा स्थिति में खलल पड़ा और बातचीत की संभावनाओं को प्रभावित किया। घटना के बाद रूस ने वार्ता की संभावना को कम कर दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पुतिन ने स्पष्ट किया है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल उन दस्तावेजों के आधार पर जो पहले से सहमत हो चुके हैं। उनका कहना है कि अस्थायी और नई मांगों पर चर्चा नहीं होगी।

रूस का साफ कहना है कि वार्ता के लिए पूर्व में सहमत दस्तावेज और शर्तों के आधार पर ही चर्चा की जाएगी। इस संघर्ष के कारण वैश्विक समुदाय, विशेषकर यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और राजनयिक दबाव डाला है। इसके साथ ही यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

क्या है इस्तांबुल समझौता?

2022 में इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई वार्ता के दौरान एक समझौते पर सहमति बनी थी, जिसे दोनों पक्षों ने प्रारंभ किया था। इस समझौते में संघर्ष को कम करने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, इस समझौते को लागू नहीं किया जा सका, और दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा। पुतिन का कहना है कि वह केवल इसी समझौते के आधार पर बातचीत के लिए तैयार हैं, और किसी भी नई मांग या शर्तों को मानने से इंकार करते हैं।

एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही गिरा, कोई नुकसान नहीं

वैज्ञानिक बोले- खतरा नहीं था, अनुसंधान के लिए मिला अहम डेटा

वॉशिंगटन (ईएमएस)। कल ऐसी दुर्लभ घटना घटित जब 2014 आरडब्ल्यू1 नाम का क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। नासा ने बताया कि करीब एक मीटर व्यास वाला यह क्षुद्रग्रह भारतीय समयानुसार बुधवार रात 10 बजकर 9 मिनट पर फिलीपींस के लूजोन द्वीप के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल गया। इस क्षुद्रग्रह को सबसे पहले कैटालिना स्काई सर्वे ने बुधवार सुबह खोजा था।

वैज्ञानिकों के मुताबिक जलने से पहले यह क्षुद्रग्रह 63,360 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से फिलीपींस के सबसे उत्तरी द्वीप के ऊपर आकाश में चमक रहा था। खगोलविदों का मानना है कि इस आकार के एस्टेरॉयड करीब हर दो सप्ताह में पृथ्वी से टकराते हैं। नासा का कहना है कि यह दुर्लभ है कि उन्हें वायुमंडल में प्रवेश से पहले कभी देखा जा सके। नासा ने पहले ही कहा था कि एस्टेरॉयड का धरती के वायुमंडल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्तरी फिलीपींस के पूर्वी तट पर यह आग के एक गोले में तब्दील हो जाएगा।

इसके असर वाले क्षेत्र में पर्यवेक्षकों को एस्टेरॉयड के विघटित होने पर एक आग के गोले को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तरी फिलीपींस को प्रभावित कर रहे टाइफून यागी ने इसमें बाधा डाली। टाइफून तूफान तीन श्रेणी में बदल गया। इसने उत्तरी फिलीपींस के आसमान में बादलों का घेरा कर दिया था, जिससे यह दृश्य आंशिक रूप से बाधित हो गया।

वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्टेरॉयड के छोटे आकार के चलते यह खतरा नहीं था। इस घटना ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अहम डेटा प्रदान किया है। इसने पृथ्वी के निकट छोटी वस्तुओं की पहचान करने की वर्तमान ट्रैकिंग सिस्टम की क्षमता को प्रदर्शित किया है। अधिकारियों ने लूजोन और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। हालांकि, घटना के बाद कोई मलबा या क्षति की सूचना नहीं है। धरती के पास से अक्सर एस्टेरॉयड गुजरते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं।

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में हो रहे हैं बदलाव, जिसके लिए देश तैयार हैः दास

उन्नत अर्थव्यवस्था बनने हमारे देश की यात्रा को कई कारकों के अनूठे मिश्रण से मिल रहा है बल

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने गुरुवार को एफआईबीएसी 2024 के उद्घाटन भाषण में कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में व्यापक पर बदलाव हो रहे हैं और देश इन बदलाव के लिए तैयार है। दास ने कहा ?कि उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारे देश की यात्रा को कई कारकों के अनूठे मिश्रण से बल मिल रहा है। इन कारकों में युवा व ऊर्जस्वी आबादी, जुझारू व विविध अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और उद्यमशीलता व नवाचार की समृद्ध परंपरा शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की वृद्धि गाथा अक्षुण्ण है और बैंकों का बहीखाता मजबूत है। दास ने निजी क्षेत्र से व्यापक स्तर पर निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। गवर्नर ने कहा कि आंकडों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी वृद्धि कारक वास्तव में गति पकड़ रहे हैं और वे धीमे नहीं पड़ रहे हैं। इससे हमें यह कहने का साहस मिलता है कि भारतीय वृद्धि की गाथा बरकरार है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) जैसे सुधारों से दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

उन्होंने भूमि, श्रम तथा कृषि बाजारों में और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गवर्नर ने कुल मुद्रास्फीति के मायने स्वीकार करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच सही संतुलन कायम है। बेहतर मानसून तथा खरीफ की अच्छी बुवाई से खाद्य मुद्रास्फीति का परिदृश्य अधिक अनुकूल हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र को समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मंच तक पहुंच बढ़ानी चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जोखिम निर्धारण मानकों को कमजोर किए बिना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम (एमएसएमई) के अनुरूप उत्पाद तथा सेवाएं पेश करने की भी वकालत की। दास ने कहा कि विवेकपूर्ण ऋण सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) मंच पर केवल विनियमित संस्थाओं को ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा ?कि यूएलआई कुछ चुनिंदा कंपनियों का क्लब नहीं होगा।

भारत में मुंह पर ताला लगा कर रहे हसीना.....राजनैतिक बयानबाजी सही नहीं

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश में पांच अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। इस बीच बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को लेकर कड़ा बयान दिया है।

यूनुस का कहना है कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं, जो सही नहीं है। उन्हें दोनों मुल्कों के बीच सौहार्द को बनाए रखने के लिए मुंह पर ताला लगाकर बैठना होगा। हम भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले हैं। यूनुस ने कहा कि अगर भारत हसीना को उनके बांग्लादेश प्रत्यर्पण तक रखना चाहता है तब इसके लिए शर्त यही है कि शेख हसीना को चुप रहना होगा। यूनुस ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि बांग्लादेश, भारत के साथ मजबूत संबंधों को तरजीह देता है। भारत को भी उस नैरेटिव से ऊपर उठकर देखना होगा, जिसमें वह अवामी लीग को छोड़कर बांग्लादेश की अन्य पार्टियों को इस्लामिक पार्टियों के तौर पर देखता है। भारत सोचता है कि हसीना के बिना बांग्लादेश एक तरह से अफगानिस्तान में तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत में शेख हसीना के रुख से सहज नहीं है। हम उनका जल्द से जल्द प्रत्यर्पण चाहते हैं ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। अगर वे भारत में चुपचाप बैठती तब हम उन्हें भूल चुके होते। बांग्लादेश के लोग भी उन्हें भुला चुके होते लेकिन भारत में बैठकर वह लगातार बयान दे रही हैं। यह किसी को पसंद नहीं है। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिवारों को आरक्षण मिलता था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई थी। इस कोटे के खिलाफ वहां उग्र प्रदर्शन शुरू हुए थे।

रूस-यूक्रेन जंग के बीच जगी शांति की उम्मीद...भारत-चीन-ब्राजील कर सकते हैं मध्यस्थता

पुतिन बातचीत के लिए राजी, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं

मास्को/कीव/नई दिल्ली(ईएमएस)। रूस-यूक्रेन जंग के करीब ढाई साल बाद शांति की उम्मीद जगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर

आंदोलन पर उतरे भावी शिक्षकों का आंदोलन खत्म, शिक्षा मंत्री ने भर्ती को लेकर किया बड़ा ऐलान

गांधीनगर,5 सितंबर,

टीएटी हायर सेकेंडरी भर्ती के लिए अधिसूचना 1 सितंबर को जारी होनी थी, लेकिन तय तिथि के अनुसार जारी नहीं होने पर टीईटी-टैट अभ्यर्थी शिक्षक दिवस पर गांधीनगर में एकत्र हुए और सचिवालय को घेरने की कोशिश की। इसलिए पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया. हालांकि, तत्कालीन शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोल ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से कहा कि नई भर्ती की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि सरकार अभी पुराने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में है. उन्होंने अगली बार दिवाली से पहले शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देने का आश्वासन दिया।

हालांकि, यहां बता दें कि बुधवार अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी. फिर उन्होंने कहा कि अभी भी आरआर. तैयार नहीं। फिर आज शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि नई भर्ती आरआर तैयार है और उम्मीदवारों के आंदोलन के कारण जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

पिछले महीने सरकार ने टीएटी और टीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद सरकारी स्कूलों में 24,700 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसमें कंप्यूटर जैसे विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा नहीं की गई थी। टीएटी हायर सेकेंडरी भर्ती के लिए अधिसूचना 1 सितंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन तारीख के अनुसार जारी नहीं होने के कारण, टीएटी-टीएटी उम्मीदवारों ने शिक्षक दिवस पर गांधीनगर में अलार्म बजाया है।

आंदोलन के लिए गांधीनगर सचिवालय पहुंचे 25 अभ्यर्थियों को गेट नंबर 1 से हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य अभ्यर्थी गांधीनगर में सीएच 3 सर्कल के पास एकत्र हुए और रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। भर्ती में सीटें बढ़ाने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर नारे लगाए।

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने अगस्त-2024 से दिसंबर-2024 तक विभिन्न चरणों में 24,700 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है और कुछ विषयों के शिक्षकों की घोषणा के अभाव में, विभिन्न विषयों के शिक्षक संघों और संघों को सरकार के खिलाफ लिखित और आमने-सामने अभ्यावेदन आ रहे हैं

शिक्षक दिवस पर गुरुजनों का ऋण स्वीकार

गांधीनगर 05 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुजनों के सामाजिक दायित्व का ऋण स्वीकार करते हुए शिक्षक कल्याण कोष में अपना योगदान अर्पित किया। गांधीनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल और स्कूल ऑफ अचीवर्स के बच्चे शिक्षक कल्याण कोष में स्वैच्छिक योगदान लेने के लिए आज सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे।

उल्लेखनीय है कि आजीवन शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

व्यक्ति और समाज के निर्माण में शिक्षकों के योगदान का ऋण स्वीकार करते हुएहर कोई इस दिन शिक्षक कल्याण कोष में अपना स्वैच्छिक योगदान देता है।मुख्यमंत्री ने भी शिक्षक दिवस के अवसर परअपना योगदान अर्पित कर गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने योगदान लेने के लिए आए स्कूली बच्चों के साथ सहज संवाद किया और शिक्षकों के प्रति अपने आदरभाव का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री मेहुल दवे, जिला विकास अधिकारी श्री जे.बी. पटेल, जिला शिक्षक अधिकारी डॉ. भगवानभाई प्रजापति, प्राथमिक शिक्षक अधिकारी श्री पीयूष पटेल सहित कई अन्य अधिकारी और स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहे।

राज्यस्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक समारोह

राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 शिक्षकों को 'श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक' से सम्मानित किया

गांधीनगर 05 सितंबर

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि यदि एक शिक्षक समर्पणभाव और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षक की शक्ति अपार होती है। शिक्षा से बड़ा पवित्र कर्म दूसरा कोई नहीं होता। शिक्षक का दायित्व इस सृष्टि में श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता और परिवार निर्माता होता है। शिक्षक सुख और शांति का आधार होता है।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अहमदाबाद के टैगोर हॉल में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 28 शिक्षकों को 'श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक' से सम्मानित किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना शिष्यवृत्ति और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले 10 लाभार्थी विद्यार्थियों को भी प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. कुबेरभाई डिंडोर और शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानशेरिया भी मौजूद रहे।

गुरुकुल के आचार्य के रूप में 35 वर्षों तक विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य की शिक्षा देने वाले राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पुस्तक 'केळवे ते केळवणी' में लिखा है कि, यदि शिक्षक अपने कर्तव्यों का योग्यतापूर्वक पालन नहीं करता है, तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। उन्होंने शिक्षकों से केवल परिचयात्मक ज्ञान के बजाय ऐसा ज्ञान देने का अनुरोध किया जो आचरण और अनुसरण में आ सके। अहिंसा और सत्य जैसे सद्गुणों का ज्ञान इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि वह जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, आभूषण बन जाए।

महर्षि उद्दालक और राजा अश्वपति कैकेय की एक घटना का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों, आचार्यों-गुरुजनों के प्रभाव से राजा कैकेय के राज्य में एक भी चोर, व्यसनी, अनपढ़, दुराचारी या कंजूस व्यक्ति नहीं था। ऐसा एक भी घर नहीं था, जहां सुबह-शाम होम-हवन न होता हो। शिक्षक ही राज्य में ऐसी स्थिति का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि छोटे से छोटा बच्चा भी सब कुछ समझता है। उसकी समझ और ग्राह्य शक्ति अमाप होती है। उन्होंने कहा कि हवन की समिधा (लकड़ी) जैसे प्रज्वलित होने को तत्पर बच्चों को विद्यापुंज जैसे अग्निस्वरुप आचार्य-गुरुजन प्रज्वलित करें और उनके अज्ञानरुपी अंधकार को दूर करें। अध्यापकों पर बड़ी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने श्रेष्ठ शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे में यदि शिक्षक भी श्रेष्ठ मानव के निर्माण के मिशन में जुट जाएं, तो हम 'विश्वगुरु भारत' का निर्माण कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शिक्षक सम्मान के इस अवसर पर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए पीढ़ी का निर्माण कर रहे शिक्षकों की कार्यनिष्ठा की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर गर्व के साथ कहा कि हमारे शिक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस विश्वास को चरितार्थ करने का दायित्व निभा रहे हैं, कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और भारत उसका नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि सामर्थ्यवान गुरु, ज्ञान और शिक्षा-दीक्षा से विद्यार्थी को तेजोमय बनाकर ईश्वर से उसका साक्षात्कार करा सकता है। बालक अपना अधिकतर समय शिक्षक के साथ बिताता है, तब शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालक की जिज्ञासावृत्ति को संतुष्ट करे। इतना ही नहीं, शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वह बालक की जिज्ञासावृत्ति और ज्ञान-कौतूहल को संतुष्ट करने के लिए समयानुकूल व्यवस्था के साथ स्वयं को भी तैयार रखे।

उन्होंने शिक्षक समुदाय की सुदीर्घ सेवापरायणता को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि, 'शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उसके अंदर का शिक्षकत्व सतत जागृत रहता है।' मुख्यमंत्री ने वल्लभी, तक्षशिला और नालंदा जैसी हमारी प्राचीन विद्यापीठों की विरासत तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल जैसे आधुनिक आयामों के समन्वय से प्रधानमंत्री के मंत्र 'विकास भी, विरासत भी' को साकार करने में गुजरात के नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात ने विद्यार्थी की शिक्षा और शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का समर्पण और शिक्षक-विद्यार्थी के बीच अपनेपन की त्रिवेणी से ज्ञान-कौशल एवं शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को उज्ज्वल एवं विकसित भारत के निर्माण में उत्प्रेरक बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने शिक्षा की दिशा बदलने के जो अभियान चलाएं हैं, उसमें कन्या केळवणी, शाला प्रवेशोत्सव, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और टीचर्स यूनिवर्सिटी आदि की सफलता में शिक्षक समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने अवॉर्ड विजेता एवं सभी शिक्षक समुदाय को बधाई देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षकों के पेशे में सामाजिक जीवन में मूल्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण का उम्दा कार्य समाहित है, जिसे हमारे गुरुवर्य भलीभांति निभाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. कुबेरभाई डिंडोर ने सरस्वती के साधक राज्य के श्रेष्ठ शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक समाज की श्रेष्ठ पूंजी हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में पूरा देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है, वह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक ही थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक में शिक्षा को उजागर करने का सामर्थ्य होता है।

6 सितंबर से गुजरात के तरणेतर मेले का प्रारंभ,लगेगा उत्तम नस्ल के पशुओं का मेला

गांधीनगर 05 सितंबर : मेले भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा हैं, जो हमारी परंपराओं, खान-पान, रहन-सहन और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले की चोटीला तहसील के तरणेतर गांव में आयोजित होने वाला तरणेतर का मेला गुजरात की जीवंत संस्कृति और परंपराओं का एक शानदार उदाहरण है।

लोककथाओं के अनुसार द्रौपदी स्वयंवर के समय तरणेतर स्थित त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में अर्जुन नेजलकुंड में मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख भेदी थी औरद्रौपदीसे विवाह किया था, इसलिए इस भूमि को पांचाल भूमि के रूप में जानाजाता है। इसजलकुंड में डुबकी लगाने का धार्मिक महात्म्य भी है। मान्यतानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहां गंगामैय्याका अवतरण होता है। किंवदंती के अनुसारतरणेतर मेला प्राचीन काल से यहांआयोजित होता चला आ रहा है।

तरणेतर मेलेमें सौराष्ट्र की विभिन्न जातियां, जैसे कि भरवाड़, आहिर, रबारी और काठी के अलावा स्थानीय लोग अपनीपरंपरागत पोशाक में भाग लेते हैं। चटख रंगों और कशीदाकारी से सजी हुई वेशभूषा में सजे युवाओं का उत्साह सातवें आसमान पर होता है। युवक रंग-बिरंगी और कढ़ाई की हुई आकर्षक छतरियों को लेकर मेले में घूमते नजर आते हैं। वहीं, युवतियांरंग-रंगीले औरघेरदार चणिया (घाघरा) को लहराते दिखाई पड़ती हैं। गरबा और डांडिया रास जैसे पारंपरिक नृत्यों में थिरकती युवतियों को देख लोग मंत्रमुग्ध जाते हैं, जबकि युवक आकर्षक छतरी नृत्य के जरिए माहौल में जोश भरते हैं।

गुजरात सरकार के पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत की ओर से तरणेतर में पशु प्रदर्शनी और प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें गिर और कांकरेज नस्ल की गाय, जाफराबादी और बन्नी नस्ल की भैंस आदि का प्रदर्शन और उत्तम नस्ल के पशुओं के लिए प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कियाजाता है। विजेता पशु को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कियाजाताहै। इसपशु मेले के आयोजन का उद्देश्य अच्छी नस्ल के पशुओं के पालन को बढ़ावा देना है।

राज्यसरकारद्वारा गुजरात में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रमचलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में,तरणेतरमेलेमेंग्रामीणयुवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देनेके लिए ग्रामीणओलंपिक काआयोजन कियाजा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के स्कूली बच्चों केलिए 100 मीटर,200 मीटर, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद,रस्सी कूद और लंगड़ी जैसे खेलों का आयोजन किया गया है।

अहमदाबाद में छह विदेशी छात्रों की अनूठी समाज सेवा, वंचित बच्चों की मदद

अहमदाबाद, 5 सितंबर

वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के आज के युग में शिक्षा एक जरूरी जरूरत बन गई है. आज भी भारत के कई पिछड़े इलाकों में बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। इस समस्या को हल करने का एक और प्रयास न केवल स्थानीय लोगों द्वारा, बल्कि विदेशी छात्रों द्वारा भी किया जा रहा है। अहमदाबाद के पिछड़े इलाकों में गरीब बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सड़क शिक्षा पहल 'प्रयास' में छह अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हुए हैं। कर्मा फाउंडेशन के सहयोग से जापान, ताइवान, मोरक्को, रोमानिया और केन्या के छह छात्र लंबे समय से बुनियादी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

आज भारत में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालाँकि, पूर्ण साक्षरता हासिल करने में अभी भी 30 साल तक का समय लग सकता है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दशक में भारत की साक्षरता दर में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जो 2023 में 77.7 फीसदी दर्ज की गई है. अनुमान है कि भारत 2060 तक सार्वभौमिक रूप से साक्षर देश बन जाएगा। गुजरात की कुल साक्षरता दर 82.4 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 92.81 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 74.8 प्रतिशत है। जो अभी भी पुरुष और महिला शिक्षा के बीच असमानता को दर्शाता है।

अनुमानतः गरीबी, बच्चों के लिए बहुत कम या न के बराबर शिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण आज भी साठ लाख बच्चों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है। कर्मा फाउंडेशन की संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी प्रियांशी पटेल ने कहा, ''अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का यह हस्तक्षेप वैश्विक समझ पैदा करके शिक्षा में असमानताओं को दूर करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनकी प्रतिबद्धता ने इन बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है।

ये छह छात्र मकु मिउरा (जापान), यूरा मात्सुबो (जापान), अकाने सुमी (जापान), सु मिंग मिंग (ताइवान), मिरेल वासेल (रोमानिया), सौहौहोएब बेन्यासी (मोरक्को) अलग-अलग परिस्थितियों से आते हैंऔर प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय कौशलहैं। और उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं. एक छात्र मकू मिउरा ने कहा, ''हम अहमदाबाद के बच्चों के साथ सीखने और बातचीत करने की उत्सुकता से प्रेरित हैं। इस अनुभव ने मुझे जीवन बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति का एहसास कराया और मैं इस प्रयास का हिस्सा बनकर धन्य महसूस करता हूं।

साबरमती से पानी छोड़े बिना बनी 11 किलोमीटर लंबी 'झील', गांधीनगर में दोनों किनारों पर बह रही धरोई

गांधीनगर,5 सितंबर

हाई अलर्ट पर संत सरोवर बांधः गांधीनगर में साबरमती नदी दो किनारों पर बह रही है. गांधीनगर के पास संत सरोवर पानी के प्रवाह के कारण 94 प्रतिशत से अधिक भर गया है। संत सरोवर में 8.7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। संत सरोवर में अपस्ट्रीम से पानी आने से गांधीनगर से लेकावाड़ा तक नदी में 11 किमी. एक कृत्रिम झील बनाई गई है।

गांधीनगर से होकर गुजरने वाली साबरमती में इस बार जुलाई के अंत में नया नीर आया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण गांधीनगर में अगस्त की शुरुआत से ही साबरमती नदी दोनों किनारों पर बह रही है। गांधीनगर से होकर गुजरने वाली साबरमती नदी का पानी संत सरोवर में जमा हो रहा है. पिछले कई दिनों से संत सरोवर का जलस्तर हाई अलर्ट यानी 90 फीसदी तक पहुंचगया है. संत सरोवर में इस समय जलस्तर 55.10 मीटर है. वर्तमान में संत सरोवर में संग्रहित जल की मात्रा 8.7 मिलियन घन मीटर है।

लाकारोदाबैराज से पानी लगातार गांधीनगर के संत सरोवर में बह रहा है। पिछले कई दिनों से एक-दो गेट खोलकर धोलेश्वर की ओर पानी छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इसबार भी गांधीनगर में साबर मती नदी धरोई बांध से पानी छोड़े बिना दो किनारों पर बह रही है.

गांधीनगर में साबरमती नदी पर बना संत सरोवर जहां लबालब हो गया है, वहीं लाकारोदा बैराज में अभी भी मानसून के बीच पानी की लगातार आवक हो रही है। इस बीच संत सरोवर के दो गेट खोलकर 2600 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. इसके चलते गांधीनगर के धोलेश्वर की ओर भी नदी में पानी का बहाव काफी तेज देखा जा रहा है. लोग यहां नहाने, मछली पकड़ने, फोटो खींचने और घूमने के लिए आते हैं, जो खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है।

गुजरात सरकार का राज्य के 21 जिलों में सरकारी पुस्तकालय शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय

गांधीनगर (ईएमएस) पुस्तक पढ़ने के महत्व को ध्यान में रखते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नागरिकों के लिए 'वाँचे गुजरात' (पढ़े गुजरात) अभियान शुरू करवाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के सभी पुस्तकालयों को ग्रंथों-पुस्तकों से समृद्ध बनाने का कार्य किया था। आज वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भी नरेन्द्र मोदी के इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाल ही में राज्य के 21 जिलों की 50 तहसीलों में सरकारी पुस्तकालय शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया है, जो अत्यंत गौरव का विषय है। उल्लेखनीय है कि हर साल 6 सितंबर का दिन 'नेशनल रीड अ बुक डे' यानी 'राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ें दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पढ़ने के आनंद का उत्सव मनाना और पढ़ने की गतिविधियों में लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।

आदिजाति बहुल क्षेत्रों के लिए पुस्तकालयों को स्वीकृति

राज्य के आदिजाति बहुल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लोगों में पठन के प्रति जागरूकता लाने तथा उन्हें पठन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य की सभी आदिजाति तहसीलों में भी पुस्तकालय कार्यरत करने की योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के आदिजाति बहुल 7 जिलों की 14 तहसीलों में पुस्तकालय शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप गुजरात की प्रत्येक आदिजाति तहसील के सभी आदिवासी समुदायों को पठन सेवा का 100 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय शुरू करने पर भी राज्य सरकार ने विचार किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने समाज के पठन प्रेमी नागरिकों को सार्वजनिक ग्रंथालय की सुविधाएँ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष राज्य में अधिक से अधिक अनुदानित ग्रंथालय शुरू करने का आयोजन किया है तथा सरकारी तहसील ग्रंथालय शुरू करने का निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की स्थापना से लेकर आज तक एक साथ एक ही वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में ग्रंथालयों को स्वीकृति देने का यह निर्णय ऐतिहासिक है।

डैम कैपिटल एडवाइजर्स ने सेबी के पास दाखिल किया डीआरएचपी

डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। डैम कैपिटल वित्त वर्ष 2022 से 2024 तक राजस्व सीएजीआर के हिसाब से भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला निवेश बैंक है। अपने समकक्षों की तुलना में डैम कैपिटल का वित्त वर्ष 2024 में प्रॉफ़िट मार्जिन सबसे अधिक है।

वित्त वर्ष 2024 में आईपीओ और क्यूआईपी की संख्या के आधार पर 12.1ज़ बाजार हिस्सेदारी के साथ यह भारत के अग्रणी निवेश बैंकों में से एक था। डीएएम कैपिटल (i) निवेश बैंकिंग के क्षेत्रों में इक्विटी कैपिटल मार्केट्स (ईसीएम), विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए), निजी इक्विटी (पीई), और संरचित वित्त सलाहकार; और (ii) ब्रोकिंग और शोध शामिल संस्थागत इक्विटी के क्षेत्रों में वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिकनिर्गम में इन्वैस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स - मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, आरबीएल बैंक, ईज़ी एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज और नरोत्तम सेखसरिया द्वारा 32.06 मिलियन शेयरों तक की ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्रमोटर धर्मेश अनिल मेहता भी अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेच रहे हैं।

नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

18 सितंबर रात्री 12.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक शाहीबाग अंडरपास यातायात हेतु बंद रहेगा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर अंडरपास नं 73 ि कि.मी. 498/28-30 शाहीबाग अंडरपास तत्काल प्रभाव से 18 सितंबर 2024 तक रात्री 00.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु यातायात के लिए बंद रहेंगे।

सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार रहेगा। (1) दिल्ली दरवाजा और सुभाषब्रिज की ओर से आने वाला ट्राफिक, जो एयरपोर्ट-गांधीनगर की ओर जाना चाहता है, वह वाहन सुभाषब्रिज के अंत में शिलालेख फ्लैट से होकर रिवरफ्रंट का उपयोग करके रिवरफ्रंट रोड डफनाला से होकर एयरपोर्ट और गांधीनगर की ओर आवागमन कर सकेंगे।

(2) एयरपोर्ट-गांधीनगर से आने वाला ट्राफिक डफनाला रिवरफ्रंट का इस्तेमाल कर अलग-अलग मार्गो पर जा सकता है। इसके अलावा असारवा, गिरधरनगर, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर की ओर जाने के लिए शाहीबाग के रास्ते महाप्रज्ञजी ब्रिज का उपयोग करके मुख्य सड़कों पर जा सकेंगे।

(3) गिरधरनगर-असारवा की ओर से आने वाला ट्राफिक, जो गांधीनगर, एयरपोर्ट की ओर जा रहा है, वह ट्राफिक शाहीबाग से होकर एनेक्षी, गायत्री मंदिर होते हुए आर्मी कैंटोनमेंट के रास्ते एयरपोर्ट और इंदिरा ब्रिज से गांधीनगर की ओर आवागमन कर सकते हैं।

ICRA ने वेदांता की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करते हुए किया

आईसीआरए ने वेदांता लिमिटेड की दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग को डर्ष्ठ्ठ-से बढ़ाकर [ICRA]AA कर दिया है, जो कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाता है। अल्पकालिक रेटिंग की भी [ICRA]A1+पर फिर से पुष्टि की गई है।

यह अपग्रेड वेदांता समूह में दीर्घकालिक रणनीतिक विकास और वित्तीय मजबूती पर केंद्रित महत्वपूर्ण विकास के बीच हुआ है। वेदांता लिमिटेड ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का वॉर चेस्ट बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से मौजूदा नकदी भंडार, हिस्सेदारी बिक्री और अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) से हासिल लाभांश शामिल है। पिछली कुछ तिमाहियों में, वेदांता ने अपनी बैलेंस शीट को डीलीवरेज किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात में 1.9× से वर्तमान में 1.5× तक सुधार हुआ है।

वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने बकाया बॉण्ड के एक बड़े हिस्से को पुनर्वित्त करने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य समेकित इकाई की ब्याज लागत को और कम करना है। सभी डीलीवरेजिंग प्रयासों से समूह की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में भी समग्र रूप से सुधार होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में एस एंड पी ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को ण्ण्ण्+ से B-/stable में अपग्रेड किया था।

फ़िलाटेक्स फ़ैशन्स लिमिटेड का खनन कार्य करने वाली सहायक कंपनी ने हासिल किए

हैदराबाद। 4 September 2024, 2024: हैदराबाद स्थित अग्रणी सॉक्स एवं कॉटन उत्पाद निर्माता कंपनी फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड (BSE – 532022, NSE – FILATFASH) की सहायक कंपनी फिलाटेक्स माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को एक महीने में कुल मिलाकर 661 करोड़ रुपए (78,875,000 डॉलर) के निर्यात ऑर्डर हासिल हुए हैं। खनन व्यवसाय में कार्यरत कंपनी की सहायक कंपनी, फिलाटेक्स माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 29 अगस्त, 2024 को घोषणा की कि उसे 1,59,000 टन पॉलिश्ड मार्बल टाइलों की आपूर्ति के लिए गिनी गणराज्य स्थित कंपनी, सोसाइटी डीआईएमओ - बीटीपी एसएआरएल (" Sme [eryeer Sme") से 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए ऑर्डर मिला है, जिनकी कीमत 43,875,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 368 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। एसडीबीएस 14 अफ्रीकी देशों में 5000 से अधिक डीलर नेटवर्क के साथ ग्रेनाइट और मार्बल की मुख्य वितरक कंपनी है।

यह कंपनी की खनन सहायक कंपनी के लिए दूसरा निर्यात ऑर्डर है। इससे पहले 26 जुलाई, 2024 को कंपनी को 7 साल की अवधि में 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 293 करोड़ रुपये) मूल्य के 2,97,388 मीट्रिक टन सफेद मार्बल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। 29 अगस्त 2024 तक, कंपनी का बाजार पूंजीकरण 966.75 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2024 को हुई अपनी बैठक में कार्यकारी निदेशक श्रेणी में कंपनी के अतिरिक्त निदेशक और सीईओ के रूप में श्री सुनील अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने 15 जुलाई 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में 5 शेयर पर 1 शेयर में स्टॉक विभाजन को मंजूरी दी थी। ईजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद कंपनी की कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1 रुपए प्रति फेसवैल्यू के 850 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित हो गई है। कंपनी ने रुपये के अंकित मूल्य के मौजूदा 1 इक्विटी शेयर के उप-विभाजन को मंजूरी दी। 5 रुपये के 5 इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक का पूर्ण भुगतान किया गया। 1 प्रत्येक पूर्ण भुगतान। स्टॉक विभाजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 9 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है।

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1.73 करोड़ रुपए और कुल राजस्व 24.22 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 179.02 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 8.95 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

रेलवे के फ्रेट लोडिंग और कोल लोडिंग के ताजा आंकड़े

भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 अगस्त तक की रिकॉर्ड 653.22 मिलियन टन माल ढुलाई की। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में इसी अवधि के दौरान रेलवे द्वारा 634.68 मिलियन टन माल ढुलाई की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 अगस्त तक माल ढुलाई से भारतीय रेल ने कुल 71,854.08 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान रेलवे को 68,740.49 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस साल के अगस्त महीने में रेलवे दवारा कुल फ्रेट लोडिंग 126.97 मिलियन टन।

अगस्त महीने में कुल माल ढुलाई से 13,354.31 रुपये की आय अर्जित की गई है। भारतीय रेल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,591 मिलियन टन माल की लोडिंग की गई है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में फ्रेट लोडिंग से 1,68,276 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 787.58 मिलियन टन कोल लोडिंग की और एक साल में कोयले की ढुलाई का अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोल लोडिंग से रेलव